



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वर्तमान में झारखण्ड प्रवास पर हैं। बुधवार को उन्होंने हजारीबाग में भाजपा उम्मीदवार मनीष जायसवाल की नामांकन सभा को संबोधित किया। इस मौके पर मु.मंत्री भजनलाल ने दावा किया कि, झारखण्ड की सभी 14 सीटों पर भाजपा विजयी होगी।

## मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का झारखण्ड दौरा

### प्रधानमंत्री ने देश को दिलाई नक्सलवाद से मुक्ति-मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

हजारीबाग, 1 मई (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को झारखण्ड के हजारीबाग में भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल की नामांकन व आशीर्वाद सभा को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस ने लुट और झूठ की राजनीति के चलते देश को बर्बाद करने का काम किया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसान और गरीब आर्थिक सशक्तिकरण करते हुए उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ा है। इस बार लोकसभा चुनावों में जनता फिर से झारखण्ड में एन.डी.ए. को विजयी बनाएगी और मोदी प्रधानमंत्री पद पर हार्दिक लगाएंगे।

उन्होंने कहा कि, कांग्रेस अफवाहों फैलाकर जनता को भ्रमित कर रही है। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस संविधान बदलने और आरक्षण समाप्त करने का दुष्प्रचार कर रही है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हजारीबाग में भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल की नामांकन सभा को संबोधित किया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, कांग्रेस अफवाह फैलाकर जनता को भ्रमित कर रही है। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस संविधान बदलने और आरक्षण समाप्त करने का दुष्प्रचार कर रही है।

जबकि प्रधानमंत्री मोदी एवं केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि, आरक्षण को कोई भी शक्ति समाप्त नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि, कांग्रेस का, अपने घोषणा-पत्र में गढ़े गए झूठों के दम पर लोकसभा चुनाव जीतने का सपना कभी सच नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि, कांग्रेस भ्रष्टाचार एवं तुष्टिकरण की जनीनी है। यह पार्टी

देश विकास के पथ पर अग्रसर होता चला गया। प्रधानमंत्री ने गरीब व किसान कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक मोर्चे पर अभूतपूर्व कार्य करते हुए भारत का विश्व में मान बढ़ाया है।

आज देश को आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्ति प्रधानमंत्री की दूरगामी एवं स्पष्ट नीतियों के कारण ही मिली है। शर्मा ने कहा कि, भजनलाल राजस्थान में वर्ष 2014 तथा 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को सही 25 की 25 सीटें प्राप्त हुई थीं। इस बार भी प्रदेश की सभी 25 सीटों पर कमल का फूल खिलेगा। उन्होंने कहा कि, झारखण्ड में भी सभी 14 सीटों पर एन.डी.ए. विजयी होगी। उन्होंने आमजन से हजारीबाग प्रत्याशी जायसवाल को अधिक से अधिक मतदान कर विजयी बनाने की अपील की।

## आंध्र में क्या मु.मंत्री जगन रेड्डी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) कर दिया है। इस मामले में जगन मोहन रेड्डी की स्थिति मजबूत है क्योंकि वह अल्पसंख्यकों सहित जनजात के सभी वर्गों में भारी तोहफे देते रहे हैं।

एक अन्य पहलु, जिस पर टी.डी.पी., जन सेना, भाजपा गठजोड़ को ध्यान देने की जरूरत है, वह है, पुनर्जीवित हुई कांग्रेस से मिल रही चुनौती, कांग्रेस मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन वाय.एस. शर्मिला के नेतृत्व में अपना जनाधार बढ़ा रही है।

संयोग की बात है कि चंद्रबाबू नायडू वाय.एस. राजशेखर रेड्डी की एक ऐसी ही चाल का शिकार हो गए थे। राजशेखर ने फिल्म अभिनेता से राजनेता बने चिरंजीवी को वर्ष 2009 में संयुक्त आंध्र प्रदेश का चुनाव लड़ने के लिए उन्हें एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल "प्रजा राज्यम पार्टी" बनवाई थी। उस वक्त के राजनीतिक विश्लेषक याद करते हैं कि राजशेखर ने चिरंजीवी से कहा था कि वे चंद्रबाबू नायडू की बजाय उनकी आलोचना ज्यादा करें और चिरंजीवी ज्यादा से ज्यादा सत्ता विरोधी वोट काट सकें। वही हुआ चंद्रबाबू हार गए चिरंजीवी ने कुछ महीनों बाद अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया और केन्द्रीय मंत्री बन

गए। वर्ष 2009 के चुनाव में नायडू जीतने वाले थे, लेकिन चिरंजीवी ने नायडू की लुटिया डुबो दी। नायडू लगातार दो चुनाव हारे और उन्हें सत्ता में आने के लिए वर्ष 2014 में राज्य में विभाजन होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। वर्ष 2009 के चुनाव के बाद वाय.एस.आर. की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। वह जिस हैलिकॉप्टर में सवार थे, वह पहले तो लापता हुआ और फिर क्रैश हो गया। यह हादसा सितम्बर 2009 का है।

विभाजित आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी (टी.डी.पी.) ने चुनाव जीता और सन् 2019 में युवजन्म श्रमिक रायपूट कांग्रेस पार्टी (वाय.एस.आर.सी.पी.) प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने टी.डी.पी. को आम चुनावों में हराकर सत्ता संभाली। उन्होंने लोकसभा की 25 में से 23 सीटें जीतीं। अब वर्ष 2024 में वाय.एस. राजशेखर रेड्डी के बेटे ने अपने पिता को "कांजी बुक" राजनीति से प्रेरणा लेते हुए अपनी बहन शर्मिला को उसी इस तरह से राजनीति में लाए हैं, ताकि उनकी बहन उनका घर (जगन मोहन रेड्डी की घर) उार करके, सत्ता-विरोधी मतों का विभाजन कर दें और ये वोट तेलुगु देशम पार्टी को न मिल सकें।

विधानसभा चुनावों में जीत का अंतर बहुत कम होता है इसलिए कांग्रेस पार्टी जो कि राज्य में फिर से खड़ी होती देख रही है, के मुखिया के रूप में उनकी बहन का होना, मुख्यमंत्री के लिए अप्रत्यक्ष बरदान है।

कर्नाटक और अन्य तेलुगु भाषी राज्य, तेलंगाना में जबरदस्त जीत के बाद कांग्रेस आगे बढ़ रही लेकिन, आंध्र में उसकी गति इतनी भी तेज नहीं है कि वो अप्रत्याशित जीत हासिल कर सके। ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस कुछ विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है और 2 से 3 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में चुनौती दे सकती है, लेकिन उसकी मुख्य भूमिका वोट "काटने" की होगी।

तेलुगु देशम पार्टी अवश्य ही यह मान रही होगी कि कांग्रेस जगन मोहन रेड्डी को एन.डी.ए. से ज्यादा नुकसान पहुंचायेगी।

तेलुगु देशम पार्टी, जन सेना पार्टी और भाजपा आंध्र प्रदेश में एन.डी.ए. के तहत चुनाव लड़ रहे हैं।

## गृह मंत्री का डीप फेक वीडियो शेयर करने पर झारखण्ड कांग्रेस का एक्स अकाउन्ट बंद

### केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को झारखंड की कांग्रेस इकाई के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था

नई दिल्ली, 1 मई। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के डीप फेक वीडियो को शेयर करने के मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) ने झारखंड कांग्रेस के एक्स अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को राज्य कांग्रेस के हैंडल के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। जिसके बाद अकाउंट को हटा दिया गया।

इसी डीप फेक वीडियो को शेयर करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर को भी नोटिस देकर पछताछ के लिए बुलाया है। दिल्ली पुलिस ने ठाकुर को समन जारी कर 2 मई को पछताछ के लिए बुलाया है।

इससे पहले दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को बताया था कि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फर्जी भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर कथित तौर पर

# 'प्रदेश में 20 से 24 वर्ष की विवाहित महिलाओं में से 25.4 प्रतिशत विवाह नाबालिग लड़कियों के हुए हैं'

### अदालत में जनहित याचिका पेश कर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-5 की रिपोर्ट के जरिये ये चौंकाने वाले तथ्य पेश किये गये

जयपुर, 1 मई (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि वह सुनिश्चित करे कि प्रदेश में कहीं भी बाल विवाह नहीं हो। इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि इस संबंध में पंच और सरपंचों को जागरूक किया जाए कि यदि वे बाल विवाह रोकने में विफल रहेंगे तो उन्हें इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। अदालत ने रजिस्ट्रार, न्यायिक को कहा है कि वह आदेश को कांपी मुख्य सचिव सहित सभी जिला मजिस्ट्रेट को भेजे, ताकि बाल विवाह रोकने के लिए इसे पंच-सरपंच सहित अन्य अधिकारियों को भेजा जा सके। वही अदालत ने मामले में राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश बचपन बचाओ आंदोलन व 'जस्ट राइट्स फोर चिल्ड्रन एलायंस' की जनहित याचिका पर दिए। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.पी. सिंह, वजीस कुमार सिंह, अनुपम भार्गव व रचना त्यागी व अन्य पैरवी के लिये पेश हुए।

“शहरी इलाकों में 15.1 प्रतिशत, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 28.3 प्रतिशत नाबालिग लड़कियों का विवाह हुआ है।”

अदालत ने कहा है कि, इस संबंध में पंच और सरपंचों को जागरूक किया जाए कि, यदि वे बाल विवाह रोकने में विफल रहेंगे तो उन्हें इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा।

अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए रजिस्ट्रार, न्यायिक, को कहा है कि, वह आदेश की कांपी मुख्य सचिव सहित सभी जिला मजिस्ट्रेट को भेजे, ताकि बाल विवाह रोकने के लिए इसे पंच-सरपंच सहित अन्य अधिकारियों को भेजा जा सके।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-5 की रिपोर्ट के अनुसार पन्द्रह से 19 साल की लड़कियों में से 3.7 फीसदी महिलाएं मां बनी चुकी है या गर्भवती हैं। इसके साथ ही यह बताया गया कि इसी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 20 से 24 वर्ष की महिलाएं जिनकी शादी हो चुकी है, उनमें से 25.4 प्रतिशत महिलाओं

की शादी 18 वर्ष पूर्ण होने से पहले की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार शहरी इलाकों में 15.1 प्रतिशत नाबालिग लड़कियों के विवाह हुआ है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 28.3 प्रतिशत नाबालिग लड़कियों का विवाह हुआ है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि यह रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू होने के बावजूद भी प्रदेश में बाल विवाह हो रहे हैं।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि हालांकि अधिकारी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अदालत ने कहा कि पंचायती राज नियम के तहत बाल विवाह रोकना सरपंच का कर्तव्य है। याचिकाकर्ताओं की अदालत से गुहार थी कि बाल विवाह निषेध अधिकारी से उनके क्षेत्र में हुए बाल विवाह व उसे रोकने के लिए किए गए प्रयासों की रिपोर्ट मांगनी चाहिए। इसके अलावा राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि प्रदेश में बाल विवाह नहीं हों। याचिका में यह भी कहा गया कि पंच और सरपंचों सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाए कि वे बाल विवाह नहीं होना सुनिश्चित करें। इसके जवाब में राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता बी.एस. छाबा ने कहा कि सरकार बाल विवाह रोकने के लिए प्रयास कर रही है। कोई भी व्यक्ति 1098 नंबर पर बाल शोषण व बाल विवाह की शिकायत कर सकता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने इस संबंध में राज्य सरकार को निर्देश जारी किए हैं।

## टी.वी. अभिनेत्री ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्होंने सूचित किया कि वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कल्याणकारी नीतियों एवं विकास के लिए की गई पहल से प्रेरित थीं। परिणामस्वरूप, दोनों सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के “विकसित भारत” के विजन का समर्थन करने की प्रतिज्ञा ली।

विनोद तावडे ने कांग्रेस की विभाजनकारी मानसिकता की यह कहते हुए निंदा की और कहा कि विपक्ष अब “नोट जिहाद” को प्रोत्साहित करने के लिए अपने प्रचार में झूठ से भी काफी आगे निकल गया है। यह झूठा प्रचार वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के निर्देश पर फैलाया जा रहा है।

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पिछड़ा वर्ग के आक्षण में कमी करके मुस्लिम समुदाय को बांट रही है और इसके साथ ही वह चुनाव को कलंकित करने के लिए “नोट जिहाद” के मुद्दे को उठा रही है।

## 6 साल की भतीजी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बनाया है। अभियुक्त का यह कृत्य अत्यंत गंभीर अपराध है। इसके अलावा वर्तमान समय में इस तरह की घटनाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ रही हैं, उन पर नियंत्रण पाना जरूरी है। ऐसे में यदि अभियुक्त के प्रति सहानुभूति बरती गई तो इससे अपराधियों के हौसे बुलंद होंगे। इसलिए अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ललिता संजीव महलवार ने अदालत को बताया कि, 19 जून, 2023 को पीड़िता के मां ने शास्त्री नगर थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि, दोपहर के समय उसकी छह साल की बेटी मोबाइल देख रही थी, इस समय उसका देवर भी कमरे में पीड़िता के साथ था। करीब आधे घंटे के बाद पीड़िता ने आकर उसे बताया कि अभियुक्त चाचा ने उसके साथ गलत

काम किया है। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता ने भी अपने साथ हुई घटना को दोहराया। अभियोजन पक्ष की ओर से डी.एन.ए. रिपोर्ट पेश करके कहा गया कि, अभियुक्त का डी.एन.ए. पीड़िता के कपड़ों पर पाया गया है। पीड़िता के बयान और डी.एन.ए. रिपोर्ट से साबित है कि, उसने पीड़िता के साथ ज्यादती की है। सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता ने भी अपने साथ हुई घटना को दोहराया। अभियोजन पक्ष की ओर से डी.एन.ए. रिपोर्ट पेश करके कहा गया कि, अभियुक्त का डी.एन.ए. पीड़िता के कपड़ों पर पाया गया है। पीड़िता के बयान और डी.एन.ए. रिपोर्ट से साबित है कि, उसने पीड़िता के साथ ज्यादती की है। सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

## 24 घंटे में अमेठी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

खड़गे को पहले ही अधिकृत कर दिया है क्योंकि पार्टी नामों की घोषणा करने से डरती नहीं है।

## 'तृणमूल से अच्छा है कि, भाजपा को वोट दे दो'

नई दिल्ली, 1 मई। लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच दरमियाई को लेकर संशय बना हुआ था। पहले भी कई बार पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस का झगड़ा सबसे सामने आ चुका था। अब एक बार फिर दोनों पार्टियों के बीच रार छिड़ी है।

तृणमूल ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष और बहरामपुर कांग्रेस उम्मीदवार अधीर चौधरी के एक वीडियो को शेयर कर बंगाल में भाजपा-वाम-कांग्रेस की मिलीभगत का आरोप लगाया है।

वीडियो में अधीर यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि तृणमूल के बजय बीजेपी को वोट देना बेहतर है। मंगलवार को अधीर जंगीपुर कांग्रेस प्रत्याशी मूर्तजा हुसैन के समर्थन में एक एक चुनावी सभा में थे। उस बैठक में सीपीएम के राज्य सचिव और मुर्शिदाबाद के वामपंथी उम्मीदवार मोहम्मद सलीम भी मौजूद थे।

## पुष्कर की कम्पनी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सैन्थिल नायगम ने “रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड” को बताया कि “मैं एक साथ 10 राजनीतिक पार्टियों के लिए काम नहीं कर सकता। उसके लिए मेरे पास बैकअप नहीं है।” उनकी कम्पनी सिर्फ उन्हीं राजनीतिक दलों के साथ काम करती है, जिन पर वे विश्वास और भरोसा कर सकते हैं।” नायगम ने जनवरी में राजनीतिक काम शुरू किए। उनका पहला प्रमुख प्रोजेक्ट तमिलनाडू की सत्तारूढ़ द्रविड़ मुन्नेत्र कवगम (डी.एम.के.) के लिए था। उनकी टीम ने राज्य सरकार के समर्थन में द्रुक्क के दिवंगत प्रसिद्ध नेता एम. करुणानिधि का एक ए.आई. वीडियो बनाया था। तीन महीनों के भीतर ही नायगम को ए.आई. केन्ट्रेट के लिए इतने अधिक पॉलिटीकल कॉन्ट्रैक्ट मिले कि उन्हें काम को निश्चित करने पर पूर्ण करने के लिए स्टूडियो, फोटोग्राफर्स, साउण्ड इंजीनियर्स और एडिटरस हायर करने पड़े।

## गुड़ामालानी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बड़े बाजरा अनुसंधान केन्द्र की सांगत दी थी। पर अब आज के राजनीतिक समीकरणों में लोग कैलाश चौधरी की इस सांगत को ज्यादा याद नहीं कर रहे हैं। अतः भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी तीसरे स्थान पर खिसकते हुए नजर आ रहे हैं।

## राष्ट्रपति मुर्मू रामलला...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने तुरंत ही शिवसेना के प्रवक्ता के आरोप व राहुल गांधी की टिप्पणी को सरासर “झूठ” बताया हुआ कहा, राष्ट्रपति मुर्मू और पूर्व राष्ट्रपति कोविंद दोनों को ही प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण व्यक्तिगत रूप से दिए गए थे। ठाकुर ने कहा, “राहुल गांधी की टिप्पणी, बिना तथ्यों की प्रमाणीकता की जांच किए, आनन-फानन में की गई थी।”

श्रीमरा जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव, चंपत राय भी आरोप-प्रत्यारोप में कूद गये, यह कहते हुए कि, “राहुल गांधी ने बिना सच जाने, झूठ बोला था। राय ने जोर देकर कहा, “राहुल का वक्तव्य बिल्कुल आधारहीन और शरारतपूर्ण है। प्राण

प्रतिष्ठा समारोह के नियंत्रण पत्र राष्ट्रपति मुर्मू और पूर्व राष्ट्रपति कोविंद को व्यक्तिगत रूप से पहुंचाये गये थे। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों को भी निमंत्रण भेजा गया था।”

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से कुछ महीनों पहले, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की उत्तर प्रदेश की चार दिवसीय यात्रा को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। पूर्व राष्ट्रपति की यात्रा लखनऊ से शुरू होकर अयोध्या में खत्म हुयी थी और बीच में वे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़, गोरखपुर में भी रुके थे। उस समय विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया था कि, उत्तर प्रदेश चुनावों से पहले, भाजपा, कोविंद को एक दलित “आइकन” की तरह पेश करना चाहती है।

भाजपा ने आरोप लगाया कि, कांग्रेस वोटों की राजनीतिक मंशा के कारण इस मामले को दबाकर बैठी रही

बैंगलुरु, 1 मई। कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) एवं जनता दल सेक्यूलर (जदएस) गठबंधन के सचिवशील प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स वीडियोज को लेकर घमासान मचा हुआ है। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर खूब हमलावर हैं। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर कथित तौर पर सेक्स वीडियो मामले में देरी से कार्रवाई करने का आरोप लगाया जा रहा है। विपक्ष इसके पीछे कांग्रेस की राजनीतिक मंशा पर सवाल उठा रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने 26 अप्रैल को हुए पहले चरण के मतदान तक का इंतजार किया।

पार्टी मतदान से पहले वोक्कालिंगा मतदाताओं को नाराज नहीं करना चाहती थी। दरअसल कर्नाटक के सीएम सिद्धार्थैया कुरुबा समुदाय से आते हैं जो राज्य में तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। लेकिन वोक्कालिंगा और कुरुबाओं के बीच खासा बनती नहीं है। इसके अलावा, लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कर्नाटक में वोक्कालिंगा मतदाता हावी थे। ये कुछ वजहें हैं जिनके आधार पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी वे वोक्कालिंगा समुदाय से आने वाले प्रज्वल के खिलाफ कार्रवाई में देरी की। दरअसल पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के कुनबे को वोक्कालिंगा का पहला

दरअसल, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के कुनबे को वोक्कालिंगा का पहला परिवार माना जाता है। इसलिए देवेगौड़ा परिवार को वोक्कालिंगा समुदाय का अच्छा-खासा समर्थन है।

कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं कि, मुख्यमंत्री सिद्धार्थैया ने जानबूझकर इस मामले को दबाये रखा ताकि वोक्कालिंगा समुदाय के लोग सरकार से नाराज ना हो जायें।

परिवार माना जाता है।

सवाल पूछे जा रहे हैं कि मतदान पूरा होने के बाद ही सरकार का ने हस्तक्षेप क्यों किया? क्योंकि कार्रवाई में देरी से कुनबे को देश छोड़ने का

कारण के बीच मधुर संबंध हैं। केन्द्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि प्रज्वल को “सीएम और रेवन्ना के बीच हुए समझौते” के बाद विदेश जाने अनुमति दी गई थी। उन्होंने कहा, अपनी गलती को छिपाने के लिए, राज्य सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है... हममें से किसी ने भी प्रज्वल को पार्टी से निर्लंबित करने का विरोध नहीं किया है। फिर भी, कांग्रेस एनडीए पर आरोप लगा रही है।

बता दें कि सिद्धार्थैया सरकार ने दक्षिण कर्नाटक में चुनाव के बाद एक एसआईटी का गठन किया है। इस दौरान प्रज्वल सहित गौड़ा परिवार के तीन सदस्यों की सीटों पर मतदान हो